पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की विविध अपील सं.1050

==========

यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स मिलेनियम बीयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ने यू. बी. टावर्स, यू. बी. सिटी, सं 24 विट्टल माल्या रोड, बैंगलोर 560001 में जिसका पंजीकृत कार्यालय है अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय कुमार सिंह, जिनकी आयु लगभग 53 वर्ष है, स्वर्गीय सर्वदेव सिंह के पुत्र, शैल भवन के निवासी, आर. एम. एस. कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना कंकड़बाग, जिला पटना के माध्यम से।

याचिकाकर्त्ता/याचिकाकर्त्तागण

बनाम

1. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य जिसका कार्यालय विकास भवन, बेली रोड, पटना में है।
2. वाणिज्यिक कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पाटलिपुत्र।
3. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, पाटलिपुत्र।
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाटलिपुत्र।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

अधिनियम/धाराएं/नियमः

- उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993-धारा 3

संदर्भित मामलेः

- एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य-(2004) 7 एस. सी. सी. 642

- मेसर्स ए. सी. सी. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य-2015 का एम. ए. सं. 149
- यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) पी. लिमिटेड बनामराज्य-2016 (1) पी. एल. जे. आर. 147
- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। **v**. नगर निगम। - (1993) 1 एस. सी. सी. 333

अपील - बीयर स्टॉक के लिए प्रवेश कर की वापसी के लिए दायर किया गया जो टूटने के कारण खो गया था और इस प्रकार अंततः नहीं बेचा गया था।

आयोजित - जहाँ तक उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए राज्य में आयात की बात है, प्रवेश कर या वैट अधिनियम लागू करने वाले क़ानून के तहत टूटने के लिए कोई छूट नहीं दी गई है और इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य क़ानून में दी गई रियायत को कर कानून में शामिल नहीं किया जा सकता है। - इसके अलावा, यदि इस तरह के असीमित टूटने की अनुमति है तो बिना किसी टूटने के भी, धनवापसी के लिए दावा किया जा सकता है। (पैरा 9)

यह राज्य को तय करना है कि क्या ऐसा लाभ निर्धारिती को प्रदान किया जा सकता है। जब तक ऐसा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, यह निर्धारिती पर है कि वह उचित देखभाल करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई टूट न हो। (पैरा 9)

याचिका खारिज कर दी गई। (पैरा 11)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की विविध अपील सं.1050

==========

यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स मिलेनियम बीयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ने यू. बी. टावर्स, यू. बी. सिटी, सं 24 विट्टल माल्या रोड, बैंगलोर 560001 में जिसका पंजीकृत कार्यालय है अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय कुमार सिंह, जिनकी आयु लगभग 53 वर्ष है, स्वर्गीय सर्वदेव सिंह के पुत्र, शैल भवन के निवासी, आर. एम. एस. कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना कंकड़बाग, जिला पटना के माध्यम से।

याचिकाकर्त्ता/याचिकाकर्त्तागण

बनाम

1. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य जिसका कार्यालय विकास भवन, बेली रोड, पटना में है।
2. वाणिज्यिक कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पाटलिपुत्र।
3. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, पाटलिपुत्र।
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाटलिपुत्र।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
		सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
		श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश
एवं
माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

कैव निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तिथि : 24-01-2024

उपरोक्त मामले में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1. *चाहे वह उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत प्रविष्टि 52 सूची* ***II*** *के साथ पढ़ा जाए, जैसा कि इसके निरसन से पहले मौजूद था, केवल स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं का प्रवेश, 'प्रवेश कर' के उद्ग्रहण के लिए पर्याप्त, या ऐसी प्रविष्टि बिहार राज्य में उपभोग, उपयोग या बिक्री के उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए?*

2. *क्या चूंकि गोदाम में पारगमन और भंडारण के दौरान माल की कुछ मात्रा को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ऐसे स्टॉक पर जमा किए गए प्रवेश कर की वापसी का हकदार है और वैट देयता के खिलाफ समायोजन के माध्यम से वापसी को सक्षम बनाता है?*

2. निर्धारिती बीयर ब्रांडों के निर्माण में लगा हुआ है, जो बिहार राज्य के भीतर आयात और बेचे जाते हैं। अपीलार्थी बिहार राज्य के बाहर स्थित शराब बनाने के कारखानों से बीयर का आयात करते समय बीयर के आयात मूल्य पर स्टॉक हस्तांतरण प्रवेश कर जमा करता है। 16 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया प्रवेश कर राज्य के भीतर बेची जाने वाली बीयर पर देय कर पर निर्धारित किया जाता है, जो विषय वर्ष में 50 प्रतिशत की दर से था। वित्तीय वर्ष 2008-09 में, अपीलार्थी ने रुपये 2,66,86,475/- का प्रवेश कर जमा किया। आरोप है कि रूपय 12,32,966 की कीमत का बीयर पारगमन में और गोदाम में संग्रहीत होने के दौरान, टूटने के कारण नष्ट हो गया था। यह अपीलार्थी का तर्क है कि इस तरह से नष्ट किए गए स्टॉक को कभी भी बेचा, उपयोग या उपभोग राज्य के भीतर नहीं किया गया था इसलिए, भुगतान किए गए प्रवेश कर को वापस करना होगा।

3. वैट देयता के खिलाफ पूरे प्रवेश कर को निर्धारित किए जाने के आधार पर पारित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक लेखा परीक्षा आपत्ति हुई। पुनर्मूल्यांकन किया गया और नष्ट स्टॉक के मूल्य के संबंध में कर घटक को अंतिम देयता में बंद करने से इनकार कर दिया गया।

4. अपीलीय अधिकारियों ने पुनर्मूल्यांकन के आदेश की पुष्टि की जिसके खिलाफ निर्धारिती द्वारा तत्काल अपील दायर की गई थी। निर्धारिती के लिए विद्वान वकील **हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य; (2003) 1 पी. एल. जे. आर. 535** पर भरोसा किया यह तर्क देते हुए कि भुगतान किया गया प्रवेश कर कुल देयता से कम होने का हकदार होगा, जब क्षतिग्रस्त माल राज्य के भीतर नहीं बेचा गया था। **यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) पी. लिमिटेड बनाम राज्य; 2016 (1) पी. एल. जे. आर. 147,** पर भरोसा किया गया, यह तर्क देते हुए कि वस्तुओं के आयात के समय उपभोग, बिक्री या उपयोग न करने का इरादा नहीं होना चाहिए। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यवसाय को चलाने के सामान्य क्रम में, यदि स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई वास्तविक खपत, बिक्री या उपयोग नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं के आयात पर कोई प्रवेश कर नहीं लगाया जा सकता है। **इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम नगर निगम, (1993) 1 एस. सी. सी. 333** पर भरोसा किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य विधानमंडल केवल स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर लगाने के लिए सक्षम है; जिसमें मुद्दा तेल कंपनी द्वारा नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित अपने डिपो में परिवहन किए गए पेट्रोलियम उत्पादों पर नगर पालिका द्वारा नगर पालिका सीमा के बाहर डीलरों को निर्यात करने के लिए, नगर पालिका की सीमा के बाहर की सीमा में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए, जिसके भीतर गोदाम स्थित था, पर नगर पालिका द्वारा चुंगी लगाने के संबंध में था।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि **2015 के एम.ए.सं. 149** में मेसर्स **ए.सी.सी. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** दिनांकित 30.11.2023 में खंड पीठ द्वारा इस मुददे् को पूरी तरह से शामिल किया गया है। विद्ान सरकारी अधिवक्ता भी **एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य; (2004)7 एस.सी. 642** पर भी भरोसा किया।

6. इन मुद्दों को पूरी तरह से शामिल किया गया है और **एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरुप अब पूरी वस्तु नहीं है। **हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड** (ऊपर) में **2015 के एम. ए. सं. 149** (ऊपर) में विचार किया गया। **हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड** (ऊपर) पटना स्थानीय क्षेत्र में लाए गए सामान को अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यक्तियों को बेचा गया और स्टॉक को राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार यह स्थापित किया जाता है कि माल को स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, बिक्री या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में नहीं लाया गया था। तब भी, यह पाया गया कि यह विक्रेता को निर्धारण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित करना था, कि आयात पुनः निर्यात के उद्देश्य से था न कि स्थानीय क्षेत्र के भीतर खपत, बिक्री या उपयोग के लिए **यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) पी. लिमिटेड में निर्णय और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन** (दोनों ऊपर) भी केवल उक्त प्रभाव के लिए थे।

7. हम **यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) पी. लिमिटेड** (उपरोक्त) में खंड पीठ की राय से पूरी तरह सहमत है कि वस्तुओं के आयात के समय उपभोग, बिक्री या उपयोग न करने का इरादा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा **यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) पी. लिमिटेड** (उपरोक्त) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि माल को बिक्री के लिए राज्य में लाया गया था, जो फलदायी नहीं था, केवल इसलिए कि वे नष्ट हो गए थे। जब राज्य के स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं का आयात होता है, तो निश्चित रूप से प्रवेश कर का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि उक्त माल का स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग,

बिक्री या उपयोग नहीं किया जाता है; जैसा कि उद्धृत निर्णय में मामला था, जिसमें माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर निर्यात किया गया था, तो आवश्यक रूप से धनवापसी का दावा किया जा सकता है, जो ऐसे निर्यात पूरा किए जाने की पुष्टि के आधार पर किया जा सकता है। यह इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि है कि यदि बिहार राज्य के भीतर माल का उपयोग, उपभोग या बिक्री नहीं की जाती है, तो इस तथ्य को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

8. **2015 के एम. ए. सं. 149** (उपरोक्त) में निर्णय पर **इंडियन ऑयल कॉर्पो** (उपरोक्त) में भी विचार किया गया। **2015 का एम. ए. सं. 149** (ऊपर) जैसा कि पैरा 18 से 20 से देखा जाता है में निर्णय नीचे दिए गए हैंः

> 18. ***इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** (*उपर्युक्त*) एक मामला है, जो प्रवेश कर के शुरु करने से संबंधित है, जब आयातित माल को आयातक के हाथों बिहार राज्य के भीतर कर के लिए आगे दायित्व का सामना नहीं करना पड़ा था। उसमें निर्धारिती ने बिहार राज्य के बाहर से कच्चे तेल का आयात किया, राज्य के भीतर अपनी रिफाइनरी में उच्च गति वाले तेल, पेट्रोल आदि का निर्माण किया और इसे पटना में अपनी शाखा में स्थानांतरित कर दिया, जहां से इसे अन्य तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बेचा गया, जो बदले में इसे खुदरा विक्रेताओं को बेचते थे, पटना के अंदर और बाहर अपने स्वयं के पेट्रोलियम आउटलेट के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं को बेचते थे, जिनकी बिक्री निर्धारिती द्वारा भी प्रभावित की गई थी। ओ. एम. सी. को की गई बिक्री पर बिहार वित्त अधिनियम, 2005 के तहत कर नहीं लगाया गया था क्योंकि एक अधिसूचना द्वारा, ओ. एम. सी. को बेचे जाने वाले

पेट्रोलियम पदार्थों पर कर लगाने के बिंदु को खुदरा विक्रेताओं और अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी बिक्री के बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी ने 16 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का भुगतान किया और वह बिक्री कर 24.5% के लिए उत्तरदायी था, जिसमें से कुल देयता, सेट-ऑफ का दावा किया गया था और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था; जो बाद में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को जन्म देते हुए उलट गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में जिन प्रावधानों को इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है, उनका प्रचुर संदर्भः

> **"13.** *चूंकि प्रश्नगत शुरुआत प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) की व्याख्या पर निर्भर करता है, इसलिए शुरुआत में यह कहना अनिवार्य है कि उक्त प्रावधान के तहत शुरुआत के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः*
>
> *(i) पहला और महत्वपूर्ण, धारा 3 (2) के तहत ही, प्रवेश कर के रूप में देय कर का भुगतान केवल वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता द्वारा किया जा सकता है।*
>
> *(ii) भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती अनुसूचित वस्तुओं का आयातक हो, जो*

वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।

(iii) *निर्धारिती को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर देयता वहन करनी चाहिए।*

(iv) *यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए; और*

(v) *वैट अधिनियम के तहत "उसकी" कर देनदारी तब अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर के सीमा तक कम हो जाएगी।*

19. वित्त अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता होने के नाते निर्धारिती को पहली शर्त को पूरा करते हुए पाया गया और हालांकि निर्धारिती माल का आयातक था, लेकिन तेल विपणन कंपनियों को अपनी बिक्री पर वैट का भुगतान करने का उसका कोई दायित्व नहीं था, इस प्रकार वह दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सका। निर्धारिती ने चौथी शर्त को भी पूरा नहीं किया क्योंकि प्रावधान में प्रयुक्त शब्द; '*या **ऐसे** आयातित अनुसूचित वस्तुएँ जिनके उपभोग द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री',* 'जो आयातक द्वारा स्वयं बिक्री को दर्शाती हैं जो अकेले पाँचवीं शर्त के अनुसार बढ़ाने का हकदार है। यह उक्ति उस तत्काल मामले में पूरी तरह से लागू होती है जहां अपीलार्थी-निर्धारिती को बिहार राज्य के भीतर आयातित

वस्तुओं पर कर नहीं देना पड़ा था, इस प्रकार अपीलार्थी को **ऐसे** आयातित सामानों की सीमा तक, जिन पर बिहार राज्य के भीतर कर नहीं लगाया गया था, भुगतान का दावा करने से अक्षम कर दिया गया था।

20. ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड*** (*उपरोक्त*) निर्धारिती द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया ***भारतीय तेल निगम लिमिटेड*** (*उपरोक्त*) से दो मामलों पर अलग था; एक, कि वहाँ एक छूट का सवाल उठाया गया था जो कर के दायित्व को समाप्त नहीं करता है और अगला कि शब्दः *'आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री या* ***ऐसी*** *आयातित अनुसूचित वस्तुओं* के उपभोग द्वारा निर्मित *वस्तुओं की बिक्री के आधार पर बाद में* ***ए. सी. सी. मामले*** में एक संशोधन के माध्यम से सेट-ऑफ देने वाले प्रावधान में जोड़ा गया। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि छूट एक रियायत है जिसे कोई भी अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि उन विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता जिनके तहत इसे दिया जाता है। इस मामले को केवल प्रवेश कर की कोई देनदारी नहीं होने के आधार पर विचार करने के लिए रिमांड पर लिया गया था क्योंकि जिस ओ. एम. सी. को अपीलार्थी ने पेट्रोलियम उत्पाद बेचे थे, उसने इसे पटना के बाहर बेचा था और इस प्रकार पटना की स्थानीय सीमा के भीतर माल का उपभोग, उपयोग या बिक्री नहीं की गई थी।

9. हम पूरी तरह से समझते हैं कि टूटने के दावे की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से, टूटने की गणना की जाती है, जो कानून में ही उपलब्ध है। जहां तक उपभोग के लिए राज्य में आयात का सवाल है, तो उपयोग या बिक्री, प्रवेश कर या वैट अधिनियम लागू करने वाले क़ानून के तहत टूटने के लिए कोई छूट नहीं दी गई है और इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य क़ानून में दी गई रियायत को कर कानून में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि इस तरह के असीमित टूटने की अनुमति है तो बिना किसी टूटने के भी, धनवापसी के लिए दावा किया जा सकता है। यह राज्य को तय करना है कि क्या ऐसा लाभ निर्धारिती को प्रदान किया जा सकता है। जब तक ऐसा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, यह निर्धारिती पर है कि वह उचित देखभाल करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई टूट न हो।

10. हम अपील पर पूर्णतया विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। कानून के प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में दिया जाना है।

11. याचिका खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायाधीश : मैं सहमत हूँ ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।